

"युद्ध अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"-वेदेल फिलिप

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 9 मार्च 2026 सोमवार

सम्पादकीय

बचपन बचाने की मुहिम

डिजिटल क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्य कर्नाटक ने सोलह साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के घातक प्रभावों से बचाने के लिये देश में सबसे पहले अनुरूपणीय पहल की है। राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि किशोरवयु अब सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय अभिभावकों की उस चिंता को कम करता है जो अनियंत्रित डिजिटल गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम से परेशान थे। जिसमें साइबर बुलिंग व साइबर धोखाधड़ी भी शामिल है। कर्नाटक की पहल के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी विधानसभा में घोषणा की है कि अगले नब्बे दिनों के भीतर 13 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी। इस तरह आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बाद ऐसा सख्त फैसला लेने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। इस प्रकार ये दो राज्य तेजी से ऑनलाइन होती दुनिया में 'किशोरों की सुरक्षा कैसे की जाए', की वैश्विक बहस में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसी पहल पहले आस्ट्रेलिया और फ्रांस आदि देशों में हो चुकी है। हालांकि, इन राज्यों की पहल सराहनीय है, लेकिन इस प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे सुनिश्चित होगा, इसका प्रारूप अभी स्पष्ट नहीं है। दरअसल, देश-दुनिया के मनोवैज्ञानिक और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया का अनियंत्रित उपयोग किशोरों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उल्लेखनीय यह है कि इस चिंता का जिफ्र 2025-26 के केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया था। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की यह पहल तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य के प्रति एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण ही दर्शाती है। लेकिन यहाँ समाज उठता है कि इस कार्य योजना को अमलीजामा कैसे पहनाया जाएगा? यह हकीकत जानते हुए कि आज के डिजिटल युग में, स्मार्टफोन और ऐप्स शिक्षा, संचार और दैनिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं।

यहाँ उल्लेखनीय है कि तमाम स्कूल असाइनमेंट और अपडेट के लिये मैसेजिंग ऐप्स, ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता बढ़ गई है। यही वजह है कि छात्रों द्वारा 'शैक्षिक' और 'सामाजिक' उपयोग के बीच अंतर करना मुश्किल साबित हो सकता है। वहीं चिंता की बात यह भी कि किशोरों की आयु का सत्यापन कैसे व्यावहारिक बनाया जा सकेगा। वहीं देखना होगा कि सोशल मीडिया को संचालित करने वाली तकनीकी कंपनियाँ किस हद तक इस दिशा में सहयोग करेंगी। सहयोग न मिलने पर प्रतिबंध की व्यावहारिकता पर सवालिया निशान लग सकते हैं। उन परिवारों में जहाँ एक ही मोबाइल फोन का परिवार के अन्य सदस्य भी उपयोग करते हैं, वहाँ प्रतिबंध की व्यावहारिकता पर सवाल लग सकते हैं। उल्लेखनीय यह है कि आस्ट्रेलिया में पहले ही सोलह साल से कम उम्र के बच्चों के लिये सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस जैसे अन्य देश भी सख्त डिजिटल सुरक्षा नियमों को लागू करने को लेकर गंभीर हैं। इसमें दो राय नहीं कि बच्चों को बेहतर डिजिटल सुरक्षा दी जानी जरूरी है, लेकिन केवल नियमित मात्र से इस जटिल समस्या का समाधान संभव नहीं हो सकता है। इस दिशा में सार्थक परिवर्तन सरकारों, स्कूलों, तकनीकी प्लेटफॉर्मों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अभिभावकों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। हालांकि, किशोरों को सोशल मीडिया की विकृतियों से बचाने के लिये तात्कालिक पहल केंद्र सरकार की तरफ से की जाती तो उसका देशव्यापी प्रभाव होता। लेकिन इसके बावजूद यदि कर्नाटक व आंध्र प्रदेश ने इस दिशा में पहल की है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा ले सकेंगे। फिर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को भी देश में एक केंद्रीय कानून लाने को बाध्य होना पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर विषय विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न वर्गों से भी राय लेनी चाहिए। ऐसे वक्त में जब बच्चों का स्क्रीन टाइम एक लत के रूप में लगातार बढ़ा है तथा उनकी एकग्रता कम होने से पढ़ाई बाधित हो रही है, तो इस संकेत का समाधान केंद्र व राज्यों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

यूपीएससी परीणामों में जामिया का दम



-अश्वित कुमार यादव-

देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल सच लोक सेवा आयोग सचिव सेवा परीक्षा के इतिहास में एक बार फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की रैंजिडेशियल कॉमिंग अकादमी (RCA) ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह वर्ष 2025 के सचिव सेवा परीक्षा परीणाम, जो इसी माह मार्च में घोषित हुए, में जामिया की इस अकादमी के 38 छात्रों ने अंतिम सूची में जगह बनाई। इन सफल उम्मीदवारों में 15 छात्रों भी शामिल हैं, जो सचिव सेवा में महिलाओं की बढ़ती मांगों का संकेत देती हैं। विशेष रूप से चार छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप-50 में स्थान हासिल किया, जिनकी रैंक क्रमशः 7, 14, 24 और 29 रही। यह उपलब्धि न केवल जामिया के लिए गौरव की बात है बल्कि यह भी दर्शाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रतिभाशाली छात्र देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँच सकते हैं।



कोविड एंड करियर प्लानिंग के अंतर्गत संचालित होती है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के प्रतिभाशाली युवाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण कोविड उपलब्ध कराना है। यहां वचनपत्र छात्रों को न केवल विशेषज्ञ शिक्षकों से पढ़ाई कराई जाती है बल्कि उन्हें हॉस्टल, लाइब्रेरी, अड्डा यमन सामग्री, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिससे वे पूरी तरह तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

RCA की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी और तब से यह सचिव सेवा की तैयारी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरी है। अपनी स्थापना के बाद से यह अकादमी सैकड़ों शिक्षित सेवाओं को तैयार कर चुकी है, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं। कई ऐसे छात्र भी रहे हैं जिन्होंने देशभर में शीर्ष रैंक हासिल कर जामिया का नाम रोशन किया है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2021 में सचिव सेवा परीक्षा की ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाली श्रुति शर्मा और वर्ष 2018 के



तीसरे स्थान पर रहे जुनैद अहमद भी इसी अकादमी से जुड़े रहे हैं। दरअसल, जामिया की RCA का मौजूद इस मामले में अलग है। कि यह केवल पढ़ाई कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को एक समग्र शैक्षणिक वातावरण प्रदान करती है। यहां प्रारंभिक परीक्षा (Pre-lim), मुख्य परीक्षा (Main) और सहाकार (Interview) के तीनों चरणों की तैयारी व्यवस्थित रूप से कराई जाती है। नियमित कक्षाओं के साथ-साथ अंतर लेखन अभ्यास, मॉक टेस्ट, विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान और पूर्व सफल अभ्यर्थियों से संचाद जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं। इस समग्र प्रशिक्षण का परिणाम है कि त. से पढ़ने वाले छात्र लगातार यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

जामिया प्रशासन के अनुसार RCA में प्रवेश भी आसान नहीं होता है, जिसके लिए हर वर्ष एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा आयोजित की

जाता है जिसमें देशभर से हजारों छात्र आवेदन करते हैं, जबकि बचन सीमित संख्या में ही होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ वर्षों में हजारों आवेदनों के बीच से लगभग 150 छात्रों को ही प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। यह चयन प्रक्रिया छात्रों की बौद्धिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और डिप्लोमा/प्लानक सोच का परीक्षण करती है।

इस वर्ष यूपीएससी परीणामों में आरसीए का प्रदर्शन इंसफ़रि भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पिछले वर्षों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने वाला है। वर्ष 2024 की सचिव सेवा परीक्षा में भी जामिया की इस अकादमी के 32 छात्रों ने सफलता हासिल की थी, जिनमें 12 छात्रों ने टॉप 100 चरण तक पहुँच कर अग्रणी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आदेश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होना जामिया की आरसीए उन्हें न केवल शिक्षा देती है बल्कि आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहकर पढ़ाई करने की सुविधा और विशेषज्ञ मार्गदर्शन उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान परीणाम में 38 छात्रों की सफलता यह दर्शाती है कि अकादमी की तैयारी पद्धति और मार्गदर्शन

नारी शक्ति का नया युग और चुनौतियाँ

-ललित गर्ग-

मानव सभ्यता के विकास की कथा में यदि किसी शक्ति ने सबसे अधिक सृजन किया है, तो वह नारी शक्ति है। यह जीवन की जगती है, संस्कृति की वाहक है और समाज की संवेदनशील आत्मा है। भारतीय परंपरा ने नारी को केवल एक सामाजिक भूमिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे माता के रूप में सर्वोच्च आदर दिया। 'मातृदेवी भव' की वाणी से लेकर 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की घोषणा तक हमारी संस्कृति में नारी के प्रति श्रद्धा का अद्वितीय भाव विराड है। यह जीवन के कि भारत में धरती, माँ और मातृभूमि तक की माना कहकर संबोधित किया गया। किन्तु विद्यमान यह है कि जिस समाज ने नारी को देवी का दर्जा दिया, उसी समाज में आज भी नारी अस्वस्थ, भेदभाव और हिंसा का सामना कर रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 हमें केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह अवसर देता है कि हम नारी की वास्तविक स्थिति का गंभीर आत्ममंजन करें। विश्व स्तर पर किए गए अड्डा यमन से यह स्पष्ट होता है कि नारी की स्थिति में प्रगति आवश्यक नहीं है, किन्तु समानता, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की वाया अभी लंबी है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में लैंगिक समानता का लगभग 68.8 प्रतिशत अंतर ही समाप्त हो पाया है, अर्थात् अभी भी लगभग एक तिहाई अंतर शेष है। आर्थिक मांगीदारी के क्षेत्र में यह अंतर सबसे अधिक है, जहाँ समानता केवल लगभग 61 प्रतिशत तक ही पहुँची है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो महिलाएँ लगभग बराबरी के स्तर तक पहुँच गई हैं, परन्तु आर्थिक अवसर और राजनीतिक नेतृत्व में अभी भी उनकी मांगीदारी सीमित है। वैश्विक स्तर पर महिलाएँ कुल कार्यबल का लगभग 42 प्रतिशत हैं और शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर उनकी हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई के आसपास है। भारत में भी स्थिति मिश्रित है। एक ओर भारतीय महिलाएँ अंतरिक्ष, विज्ञान, समानता और प्रशासन में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर श्रम बाजार



में उनकी मांगीदारी अभी भी कम है। हाल के आँकड़ों के अनुसार भारत में महिला श्रम मांगीदारी दर लगभग 32 प्रतिशत है और बाली संख्या में महिलाएँ घरेलू दायित्वों के कारण रोजगार से बाहर रहती हैं। विज्ञान स्ट्रेटजी के यह आँकड़े केवल संख्या नहीं हैं, यह समाज की संरचना, सोच और अवसरों की असमानता को उजागर करते हैं। कई ऐसे छात्रों के अनेक देशों में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और धर्मोपनिषत् के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। भारत में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक और फाउंडर पायलट के रूप में महिलाओं की उपस्थिति उच्च परिवर्तन का प्रमाण बनी है और बन रही है। किन्तु इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि दुनिया में अभी भी केवल सीमित देशों में ही महिलाएँ सर्वोच्च राजनितिक पदों पर हैं और समान वेतन का प्रश्न अभी भी अनुरा है। कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में अतिरिक्त कम वेतन मिलता है।

और और शिक्षाजनक तथ्य यह है कि संचार, युद्ध और संकेत की स्थितियों का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। हाल के वैश्विक अध्ययनों के अनुसार 2024 में लगभग 67 करोड़ महिलाएँ ऐसे क्षेत्रों में रह रही थीं जो किसी न किसी प्रकार के हिंसक संघर्ष से प्रभावित थे।

नये युग की समस्याएँ जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और डिजिटल असमानता भी महिलाओं के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। यदि इन समस्याओं पर समान रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में करोड़ों महिलाएँ और लड़कियाँ अल्पविक गरीबी की ओर धकेली जा सकती

-दीपक कुमार त्यागी-

जिस दौर में पूरी दुनिया में हर देश के हुम्बरान अवसर-अपने देश का सर्वांगीण विकास करने की दिशा में पीट रहे हों, उस दौर में विकास के नए पर हथियारों की एक ऐसी तेज दौड़ दुनिया में चल रही है, जिसने अभी तक तो कई देशों में भीषण युद्ध तक भी कराया दिया है और कई देशों को युद्ध के मुद्दाने पर लक्ष्मण के खड़ा कर दिया है, दुनिया भर में आधुनिक हथियारों व तकनीक के दम पर 21वीं सदी में युद्ध की तरह-तरह की पटकथाएँ लिखी जा रही हैं। लेकिन 21वीं सदी के आधुनिक युग में दुनिया में एक सबसे बड़े स्थल टकराव की मजबूत नींव रखने वाले ईरान, इजरायल और अमेरिका का महायुद्ध आंग्र जल्द ही नती रूका तो यह पूरी दुनिया के लिए एक सिस्टम दर्जन बन सकता है, यह युद्ध अकार्य फिर से दुनिया का नक्शा बदलने वाला साबित हो सकता है। यह युद्ध शुरूआती चढ़ घंटों के बाद ही भीषण युद्ध के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, मीडिया युद्धों के अनुसार इस युद्ध में सभी पक्षों को नेतृत्व दिन से ही जान-माल बड़ी चुनौती है। वहीं इस्लाम, तमी असमानता जन्म लेती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का वैश्विक संदेश भी इसी दिशा में संकेत करता है- "सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय और वास्तविक परिवर्तन"। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आज भी दुनिया में महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकारों का प्रदान नहीं है और अतिरिक्त उन्हें पुरुषों के मुकाबले लगभग 64 प्रतिशत ही कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ में यह स्थिति हमें सचेत करे कि यह युद्ध कहीं भी ब्रेक कानून बनाया पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कानूनों को सामाजिक चेतना में बदलना भी आवश्यक है।

तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर दुनिया



हमले से कुवैत में स्थित अमेरिका के 56 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और जिस तेजी गति से युद्ध चल रहा है आने वाले दिनों में ईरान, इजरायल-अमेरिका के साथ-साथ यह भीषण युद्ध वैश्विक स्तर पर समीकरणों के बदलाव को भीषण विश्वयुद्ध की पटकथा बन सकता है। युद्ध के साथ-साथ आगामी दिनों में इस युद्ध का भारत पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है क्योंकि युद्ध से प्रभावित अलग-अलग देशों में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिस लोगों को सुरक्षित निकाल कर भारत लाना बड़ी चुनौती है। वहीं खाड़ी देशों से जिस तरह से भारतीय विमानसेवाएँ व कामगारों हर माह भारी-भरकम धनराशि का भारक भारत भेजते हैं, आने वाले दिनों में यह भीषण विश्वयुद्ध की पटकथा बन सकता है। युद्ध के साथ-साथ आगामी दिनों में इस युद्ध का भारत पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं तेल की कीमतों में लगाती तेजी की आग से दुनिया के साथ भारत में भी मंहगाई का वेग बढ़ने की पूरी संभावना है और युद्ध की विभीषिका से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी होने की पूरी संभावना है, जो विकास के पथ पर बहुत ही तेजी से अप्रसरित भारत के लिए उचित नहीं है। वहीं जिस तरह से आधुनिक हथियारों से सुलज्जित अमेरिका सेना की एक पावरफुली ने हिन्द महासागर क्षेत्र में अकार्य और ईरान सेना के सहाज को निशाना बनाकर के ईरान के सैकड़ों नागरिकों को मार डाला है, यह भारत की संभ्रमता के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है और भारत को भी इस युद्ध में शामिल करने के एक बड़ी साजिश लगती है।

हालांकि भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में इस युद्ध का प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं खाड़ी देशों से जिस तरह से भारतीय विमानसेवाएँ व कामगारों हर माह भारी-भरकम धनराशि का भारक भारत भेजते हैं, आने वाले दिनों में यह भीषण विश्वयुद्ध की पटकथा बन सकता है। युद्ध के साथ-साथ आगामी दिनों में इस युद्ध का भारत पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं तेल की कीमतों में लगाती तेजी की आग से दुनिया के साथ भारत में भी मंहगाई का वेग बढ़ने की पूरी संभावना है और युद्ध की विभीषिका से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी होने की पूरी संभावना है, जो विकास के पथ पर बहुत ही तेजी से अप्रसरित भारत के लिए उचित नहीं है। वहीं जिस तरह से आधुनिक हथियारों से सुलज्जित अमेरिका सेना की एक पावरफुली ने हिन्द महासागर क्षेत्र में अकार्य और ईरान सेना के सहाज को निशाना बनाकर के ईरान के सैकड़ों नागरिकों को मार डाला है, यह भारत की संभ्रमता के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है और भारत को भी इस युद्ध में शामिल करने के एक बड़ी साजिश लगती है।

हालांकि भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में इस युद्ध का प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं खाड़ी देशों से जिस तरह से भारतीय विमानसेवाएँ व कामगारों हर माह भारी-भरकम धनराशि का भारक भारत भेजते हैं, आने वाले दिनों में यह भीषण विश्वयुद्ध की पटकथा बन सकता है। युद्ध के साथ-साथ आगामी दिनों में इस युद्ध का भारत पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं तेल की कीमतों में लगाती तेजी की आग से दुनिया के साथ भारत में भी मंहगाई का वेग बढ़ने की पूरी संभावना है और युद्ध की विभीषिका से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी होने की पूरी संभावना है, जो विकास के पथ पर बहुत ही तेजी से अप्रसरित भारत के लिए उचित नहीं है। वहीं जिस तरह से आधुनिक हथियारों से सुलज्जित अमेरिका सेना की एक पावरफुली ने हिन्द महासागर क्षेत्र में अकार्य और ईरान सेना के सहाज को निशाना बनाकर के ईरान के सैकड़ों नागरिकों को मार डाला है, यह भारत की संभ्रमता के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है और भारत को भी इस युद्ध में शामिल करने के एक बड़ी साजिश लगती है।

